

मध्य प्रदेश में प्राचीन बिद्युत् सहकारी समितियों के माध्यम से बिजली की सप्लाई

रूपये की अनुमानित लागत की पाँच स्कीमें स्वीकृत की हैं ।

2705. श्री गंगा चरण बोसित : क्या सिंचाई और बिद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम बिजली सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में बिजली सप्लाई करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के गांवों में बिजली सप्लाई की जा रही है ;

(ग) क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत छोटे और मध्यम बर्ग के किसानों को बिजली के कनेक्शन लेने के लिए कोई सहायता दी जा रही ; और

(घ) यदि मध्य प्रदेश में ऐसी सहकारी समितियां नहीं बनाई गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और बिद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) जी, हां। ग्राम बिद्युतीकरण निगम ने, जहां अमरीकी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर पाइलट परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं, ग्राम बिजली सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देनी शुरू कर दी है।

(ख) से (ग). जैसा कि 12 अगस्त, 1968 को लोक सभा में तारकित प्रश्न संख्या 435 के उत्तर में बताया गया था, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पाइलट ग्राम बिजली सहकारिता परियोजना की स्थापना की स्कीम अमरीकी विशेषज्ञ दल ने आगे अन्वेषण के लिए शामिल नहीं की थी क्योंकि दल को दी गई स्कीम रिपोर्ट को व्यवहार्य नहीं समझा गया था। निगम ने सिंचाई कार्यों के लिए 18,352 पम्प सेटों के उर्जन के लिये मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की 331.396 लाख

Problem of Sea-erosion in Kerala

2706. SHRI VAYALAR RAVI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the total amount spent on anti-erosion work in Kerala during the Third Plan ;

(b) whether Government propose to include the problem of Sea-erosion in the Flood Control Programme ; and

(c) whether Central Government have received any memorandum from the Kerala Government in this regard and if so, the reaction of the Central Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. N. KUREEL) : (a) The expenditure on anti-sea-erosion works in Kerala during the Third Plan was Rs. 4.46 crores.

(b) Anti-sea-erosion measures form a part of the flood control sector in the State Plan.

(c) A Memorandum has been received from the Government of Kerala that the problem of sea-erosion in Kerala should be treated as a National problem. Such requests had been received in the past also, but it had not been found possible to treat it as a National problem. The matter is, however, proposed to be taken up with the Planning Commission again.

Request for Stoppage of Mail/Express Trains at Avadi (Southern Railway)

2707. SHRI T. S. LAKSHMANAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from the several associations of travelling public requesting for the stoppage of Mail/Express trains at Avadi on Southern Railway ; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIA) : (a) Yes.

(b) The demand has not been found justified.